वस्त्र मंत्री साथ में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) संशोधित खाद्य पदार्थों के उत्पादन की कुल लागत में पैकेजिंग सामग्री की लागत अलग-अलग उत्पादों के लिए अलग-अलग है। तथापि, भारतीय पैकेजिंग संस्थान के अनुसार, अधिकांश मामलों में पैकेजिंग सामग्रियों की लागत खुदरा बिक्री मूल्य के संबंध में 20 प्रतिशत से 35 प्रतिशत के बीच में है। संशोधित खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग की लागत कम करने के लिए पैकेजिंग सामग्री, पैकेजिंग मशीनरी में करों की कमी करने और प्रौद्योगिकी का उन्नयन करने जैसे विभिन्न उपाय समय-समय पर किये जा रहे हैं।

पंजाब में फसल-पद्धति पर पेप्सी परियोजना का प्रभाव

1012. श्री अजीत जोगी :
कुमारी आलिया :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पेप्सी परियोजना से पंजाब के किसान खाद्यानों बजाय फलों की अधिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित होंगे ; यदि हां, तो क्या इससे पंजाब में फसल-पद्धति में परिवर्तन होने की संभावना है ;

(ख) क्या यह सच है कि इससे राज्य में खाद्यानों की उपलब्धता में पर्याप्त कमी होने की संभावना है और इसके फलस्वरूप, आवश्यक खाद्य-पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि होने की संभावना है ; और

(ग) इस संबंध में उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री साथ में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री शरद यादव): (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही हैं और जितनी भी उपलब्ध हो पायेगी सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नार्वे को सामान का निर्यात

1013. श्री अजीत जोगी :
कुमारी आलिया :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान नार्वे को निर्यात किए गए समान का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उक्त निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) (क) नार्वे की निर्यात की जाने वाली प्रमुख मदें है : परिधान, वस्त्र आदि, चमड़ा और चमड़े से बनी वस्तुएं, यात्रा की वस्तुएं और उपकरण काफी, चाय और मसाले।

(ख) वर्ष 1985–86 से लेकर नार्वे को किए जाने वाले निर्यात के मूल्य निम्नानुसार हैं :—

(करोड़ रुपए में)

1985–86	16.35
1986–87	17.51
1987–88	22.50
1988–89	22.05
1989–90	52.65

(स्रोत : जी.डी.सी.आई.एण्ड एस., कलकत्ता)

Annual outlay for Rajasthan Canal

1014. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA; Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state;

(a) what was the annual outlay for Rajasthan Canal Project during 1987, 1988 and 1989, year-wise and the outlay for the current year,

(b) what is the actual amount spent on the Project during these years, year-wise and during 1990 till date;

(c) what is the overall estimated cost of the Project at the current price's by the close of the financial year 1990-91; and

(d) what is the present position with regard to the completion of the project stating the Viteps contemplated by the Central Government to accelerate the process of its completion?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI MANUBHAI KOTADIA): (a) and (b)

Year	Budget Outlay for Canal works	Actual expen, diture
	(Rs. Crores)	
1987-88.	65.00*	65.00
1988-89	60.00*	52.64
1989-90 .	64.13*	56.94
1990-91 . . .	70.45*	10.31 (upto June, 1990)

♦(These figures are inclusive of the funds available under Border Area Development Grant)

The above does not include an expenditure of Rs. 111.87 crores during 1987-88 to 1989-90 and outlay of Rs. 65.78 crores during 1990-91 for CAD works.

(c) The State Government has not yet finalised the revised estimate at current prices including the command area development works.

(d) According to the State Government, the completion of the project is likely to extend to the Tenth Plan. During the Seventh Plan the Central Government provided a total assistance of Rs. 164.20 crores which is about 47 per cent of the total expenditure on Canal, and CAD works in that Plan o$_n$ Stage-Il.

Overdrafts by Tripura Government from R.B.L

1015. SHRI NARAYAN KAR; Will^ the Minister of FINANCE be pleased to state;

(a) The number of times Tripura Government resorted to overdrafts from R.B.I, in 1988 and 1989;

(b) The number of times Tripura Government resorted to overdrafts from R.B.I, in 1986 and 1987;

(c) The grounds for resorting to such frequent overdrafts; and

(d) whether the Central Government imposed any financial discipline against wasteful expenditure, if there was any?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ANIL SHASTRI): (a) and (b) The Government of Tripura did not run into overdraft with the RBI during the financial years 1986-87 and 1987-88, but went into overdraft 10 times in 1988-89 and 13 times in 1989-90.

(c) Overdrafts arose mainly on ac count of the imbalances between the flow of receipts and pace of expenditure.

(d) According to the State Govern ment, overdrafts were not due to wasteful expenditure and hence the question of Central Government imposing financial discipline against wasteful expenditure did not arise.

राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात-लक्ष्य में कमी किया जाना

1016. श्री राम जेठमलानी :
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 जून, 1990 के "फाइनेंसियल एक्सप्रैस" में "एस.टी.सी. पूल्स 90-91 टारगेट बाई रूपीज 450 करोड़स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;